

सुपौल जिला में अनुसूचित जाति का स्थानिक वितरण का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. सुदीप कुमार

ग्राम:-नादो, पोस्ट:- दमगढ़ी

थाना:- सौरबाजार, जिला:- सहरसा

परिचय :-

सुपौल जिला में अनुसूचित जातियाँ एक समाजिक व्यवस्था का अंग हैं, जिसमें अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ सम्मिलित हैं। समाज का यह वर्ग अति पिछड़ा, शोषित उपेक्षित एवं अर्थ विपन्न ग्रसित जाति है। सरकारी नीति, सहयोग एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण से कुछ परिवारों का आर्थिक, शैक्षणिक एवं समाजिक दशाओं में सुधार हुआ है, फिर भी यह जाति समूह अभी भी अन्य जाति समूहों से अधिक पिछड़ा हुआ है। सुपौल जिला में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 354249 है जिसमें 182545 पुरुष तथा 171704 स्त्री जनसंख्या है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 15.89 प्रतिशत अनुसूचित जाति है, लेकिन प्रखण्ड स्तरीय इसकी संख्यात्मक वितरण में काफी असमनता पायी जाती है।

भूमिका :-

भारतीय समाजिक व्यवस्था में विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ण व्यवस्था का इतिहास सभ्य मानव के प्रारंभिक चरण से ही रहा है। यहाँ कार्यों के आधार पर मुख्यतः चार जाति समूह हैं। इन्हीं जाति समूह में अनुसूचित जाति है, जो समाज का शोषित दलित वर्ग है। यह जाति अनेक उपजातियों का समूह है, जिसका अलग-अलग कार्यों के आधार पर जाति का नामकरण हुआ। इन्हीं जातियों में धोबी, नाई, चमार, लौहार आदि हैं। प्राचीन भारतीय समाज में विभिन्न कार्यों का सम्पादन समाज के विभिन्न वर्णों से होता था। समाज का कार्यात्मक स्वरूप इतना संगठित था कि समाज के सभी वर्गों के आवश्यकता की पूर्ति एक-दूसरे के समाजिक सहयोग से होता था। समाज में ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन-अध्यापन एवं पूजापाठ क्षत्रीयों का कार्य शासन एवं सुरक्षा, वैश्य का कार्य वानिज्य व्यापार एवं शुद्रों का कार्य सेवा भाव था। विभिन्न तकनीक की जानकारी हेतु कोई संस्था नहीं थी, वरण परिवार ही तकनीकी ज्ञान का केन्द्र होता था। जहाँ परम्परागत कार्यों सीखते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक यह व्यवस्था बनी रही, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ सभी वस्तुओं का उत्पादन एवं बाजारीकरण होने से समाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से कम बाजार से अधिक होने लगा। समाज का सबसे निचले पैदान पर स्थित अनुसूचित जातियों का वर्तमान समय तीव्रगति से उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक योगदान है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

प्रस्तुत लेख में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सुपौल जिला में शोषित, दलित, अर्थ विपन्न अनुसूचित जाति का संख्यात्मक एवं गुणात्मक पक्षों का अध्ययन आर्थिक विकास के परिपेक्ष में करना है। संख्यात्मक पक्ष में अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डवार वितरण ज्ञात करना है। गुणात्मक पक्षों में साक्षरता एवं व्यवसायिक संरचना का अध्ययन है। आर्थिक एवं समाजिक पक्षों के उत्थान का सुझाव देना है।

विधि तंत्र :-

आनुभविक विधि लेख का मुख्य आधार है, जो आँकड़ों पर आधारित हैं। आँकड़ों का संग्रह में प्राथमिक एवं द्वितीयक विधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह स्वयं सर्वेक्षण से किया गया है जिसमें समाज में अनुसूचित जातियों की दशाओं का अध्ययन किया गया। जबकि द्वितीय आँकड़ों का संग्रह भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 से किया गया। लेख के लिए पूर्व में किये गये अध्ययन पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि से अनेक तथ्यों का संग्रह किया गया है। आधुनिक तकनीकी से मानचित्र तथा आलेख बनाया गया है।

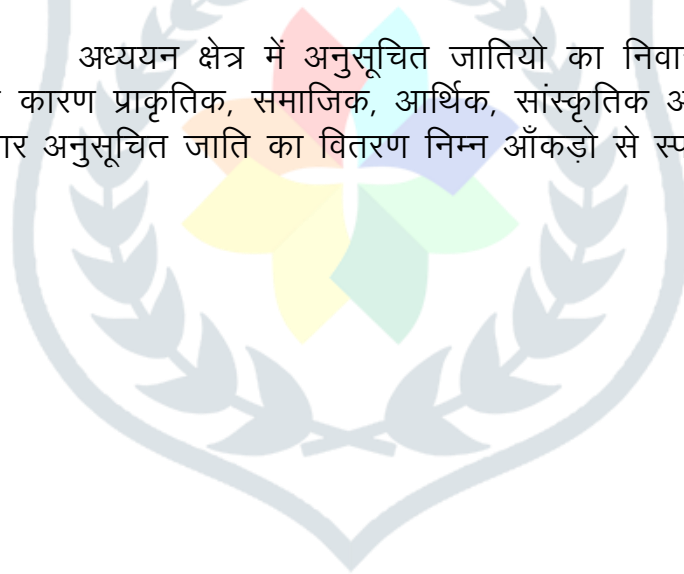
अध्ययन क्षेत्र :-

प्रस्तुत लेख का अध्ययन क्षेत्र सुपौल जिला है जो बिहार के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित पश्चिमी कोशी मैदान का एक जिला है। यह कोशी मैदान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में अवस्थित एक राजनैतिक प्रदेश है जिसका सीमांकन सुपौल जिला के सीमा से होती है। इसका सीमांकन उत्तर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल का है जबकि दक्षिण में सहरसा एवं मधेपुरा जिला पूरब में अररिया तथा पश्चिम में मधुबनी जिला के मध्य अवस्थित है। ज्यामितीय अवस्थिति में अक्षांशीय विस्तार $25^{\circ} 37'उ०$ से $26^{\circ} 25'उ०$ तथा देशान्तरीय विस्तार $86^{\circ} 22'पू०$ से $87^{\circ} 10'पू०$ तक है। इसकी लम्बाई 105 Km चौड़ाई 83 Km तथा क्षेत्रफल 2425Km^2 है। ग्रामीण क्षेत्रफल 2388Km^2 तथा नगरीय क्षेत्रफल 36.34Km^2 है। सुपौल जिला का मुख्यालय सुपौल है। सम्पूर्ण प्रदेश उपोष्ण मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में अवस्थित है।

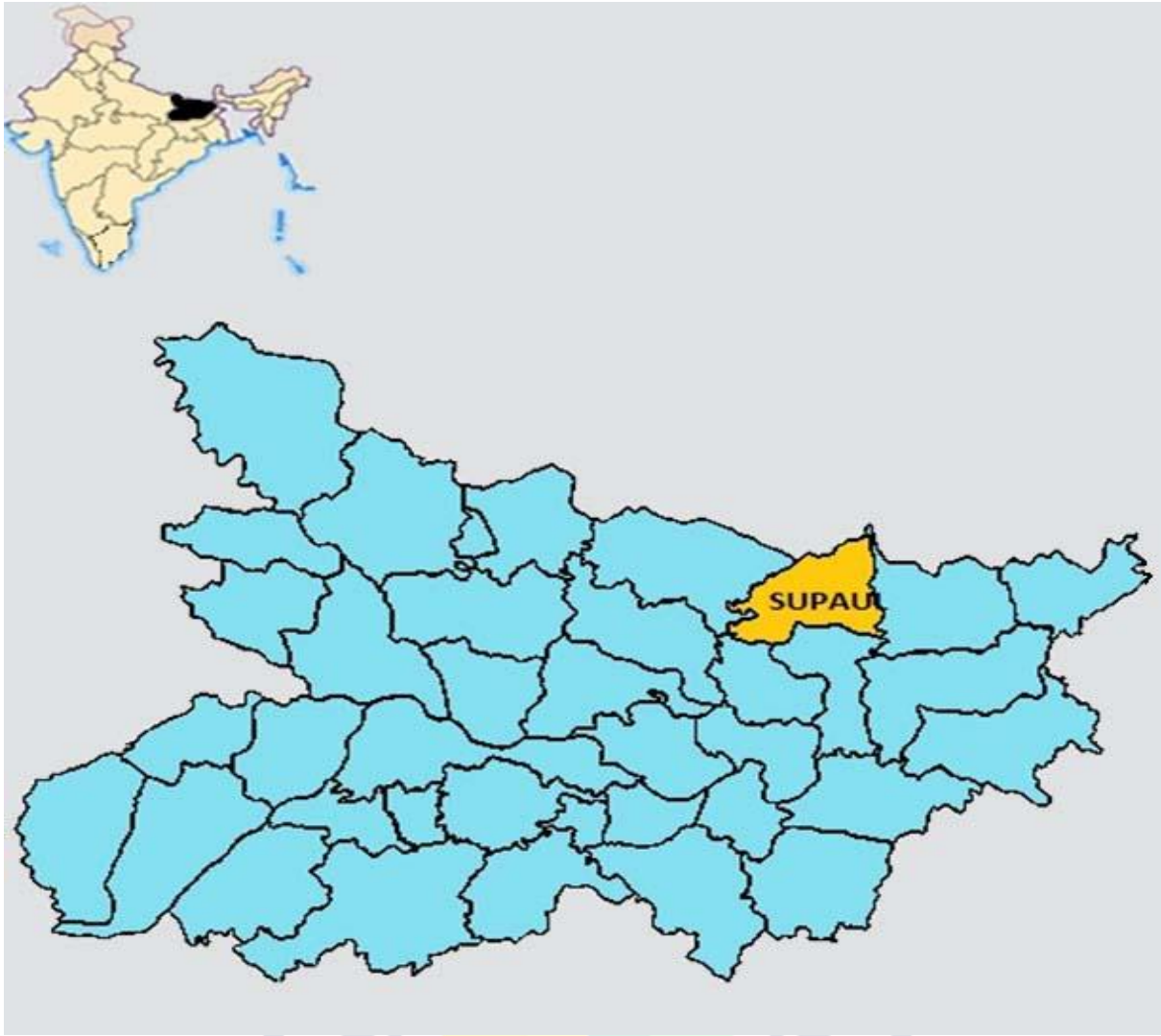
विश्लेषण :-

सुपौल जिला में अनुसूचित जाति का संख्यात्मक वितरण सभी क्षेत्रों या प्रखण्डों में एक समान नहीं है। फिर भी सम्पूर्ण जिला के प्रायः सभी क्षेत्रों में इसका वसाव है। यद्यपि इसकी संख्या अन्य जातियों की तुलना में कम है फिर भी किसी भी प्रखण्ड में वहाँकी कुल संख्या का 10 प्रतिशत कम नहीं है और न 20 प्रतिशत से अधिक है। समाजिक संघटक एवं समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए सभी वर्गों का होना अनिवार्य माना जाता था। अतः प्रायः सभी क्षेत्रों में न्यूनाधिक संख्या में सभी वर्गों के लोगों का वसाव पाया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश कोशी नदी के जलोढ़ से निर्मित उपजाऊ समतल मैदान होने के कारण मानव वसाव आदिकाल से ही रहा है। उपजाऊ मैदान होने से कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, यहाँ कृषक एवं कृषि श्रमिक का वसाव कृषि जन्य आवश्यकता रही है। अतः अधिकांश अनुसूचित समुदाय कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन आदि व्यवसाय में ये लोग संलग्न हैं। मानव वसाव उपयुक्त भौगोलिक दशाओं वाले क्षेत्रों में अधिक होते हैं जबकि अनुपयुक्त दशाओं वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम होते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का निवास एवं वितरण में असमानता पायी जाती है जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक, समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि का असमान पाया जाना है। सुपौल जिला में प्रखण्डवार अनुसूचित जाति का वितरण निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है –



LOCATION MAP OF BIHAR IN INDIA & SUPAUL IN BIHAR



Map – 1

तालिका – 1
सुपौल जिला में अनुसूचित जाति का वितरण

प्रखण्ड	अनुसूचित जाति की संख्या	पुरुष प्रतिशत में	स्त्री प्रतिशत में
निर्मली	11058	51.23	48.77
बसन्तपुर	37730	51.61	48.39
छातापुर	54770	51.54	48.46
प्रतापगंज	15131	51.54	48.46
राघोपुर	32229	51.38	48.62
सरायगढ़	17369	51.42	48.58
किसनपुर	19719	51.68	48.32
मरौना	15872	51.27	48.73
सुपौल	51258	51.70	48.30
पिपरा	34692	51.33	48.67
त्रिवेणीगंज	64419	51.57	48.43
कुल जिला	354249	51.53	48.47

स्रोत – भारत की जनगणना 2011, बिहार श्रृंखला 11

तालिका 1 में सुपौल जिला में प्रखण्डवार अनुसूचित जाति के वितरण को दर्शाया गया है। सम्पूर्ण जिला में कुल जनसंख्या 354249 है जो कुल जनसंख्या का 15.89 प्रतिशत है, परन्तु स्थानिक वितरण में असमानता पायी जाती है। प्रखण्डवार वितरण देखा जाय तो सबसे कम निर्मली प्रखण्ड में 11054 है जिसमें 51.23 प्रतिशत पुरुष तथा 48.77 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या है। दूसरी ओर सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या छातापुर में 54770 है जिसमें 51.54 प्रतिशत पुरुष तथा 48.46 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या है। अन्य प्रखण्डों में बसन्तपुर में 37730 में 51.61 प्रतिशत पुरुष तथा 48.39 प्रतिशत स्त्री की संख्या है। प्रतापगंज प्रखण्ड में कुल संख्या 15131 में 51.54 प्रतिशत पुरुष तथा 48.46 प्रतिशत स्त्री, राघोपुर प्रखण्ड में कुल संख्या 32229 में 51.38 प्रतिशत पुरुष तथा 48.62 प्रतिशत स्त्री, सरायगढ़ प्रखण्ड में कुल संख्या 17369 में 51.42 प्रतिशत पुरुष तथा 48.58 प्रतिशत स्त्री, किसनपुर प्रखण्ड में कुल संख्या 19719 में 51.68 प्रतिशत पुरुष तथा 48.73 प्रतिशत स्त्री की संख्या है। मरौना प्रखण्ड में कुल संख्या 15872 में 51.27 प्रतिशत पुरुष तथा 48.73 प्रतिशत स्त्री, सुपौल प्रखण्ड में कुल संख्या 51258 में 51.70 प्रतिशत पुरुष तथा 48.30 प्रतिशत स्त्री, पिपरा प्रखण्ड में कुल संख्या 34692 में 51.33 प्रतिशत पुरुष तथा 48.67 प्रतिशत स्त्री तथा त्रिवेणीगंज प्रखण्ड में 64419 में 51.57 प्रतिशत पुरुष तथा 48.43 प्रतिशत स्त्री की संख्या है। सभी प्रखण्डों में पुरुष की तुलना में स्त्री की संख्या 1-2 प्रतिशत कम है।

सुपौल जिला में अनुसूचित जाति का वितरण

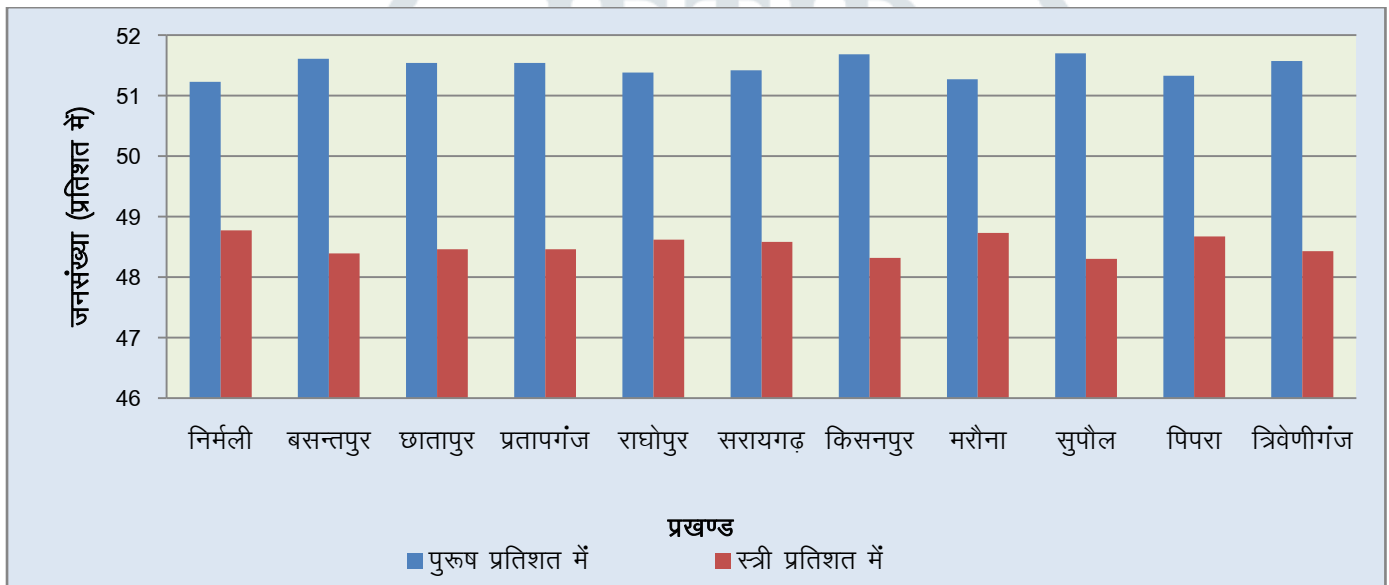


Fig. – 1

सुपौल जिला में अनुसूचित जाति का तुलनात्मक वितरण में काफी असमानताये पायी जाती है। जिला के कुल अनुसूचित जाति का प्रखण्डवार तुलनात्मक वितरण निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है –

तालिका – 2

जिला एवं प्रखण्डवार कुल अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत

क्रम संख्या	प्रखण्ड	प्रखण्ड के कुल जनसंख्या का प्रतिशत	जिला के कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	निर्मली	11.23	0.45
2.	बसन्तपुर	18.68	1.69
3.	छातापुर	19.12	2.41
4.	प्रतापगंज	14.16	0.67
5.	राघोपुर	14.95	1.45
6.	सरायगढ़	14.15	0.77
7.	किसनपुर	11.76	0.88

8.	मरौना	10.94	0.71
9.	सुपौल	14.23	2.25
10.	पिपरा	17.23	1.55
11.	त्रिवेणीगंज	19.98	2.88
कुल जिला		15.69	15.89

जिला एवं प्रखण्डवार कुल अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत

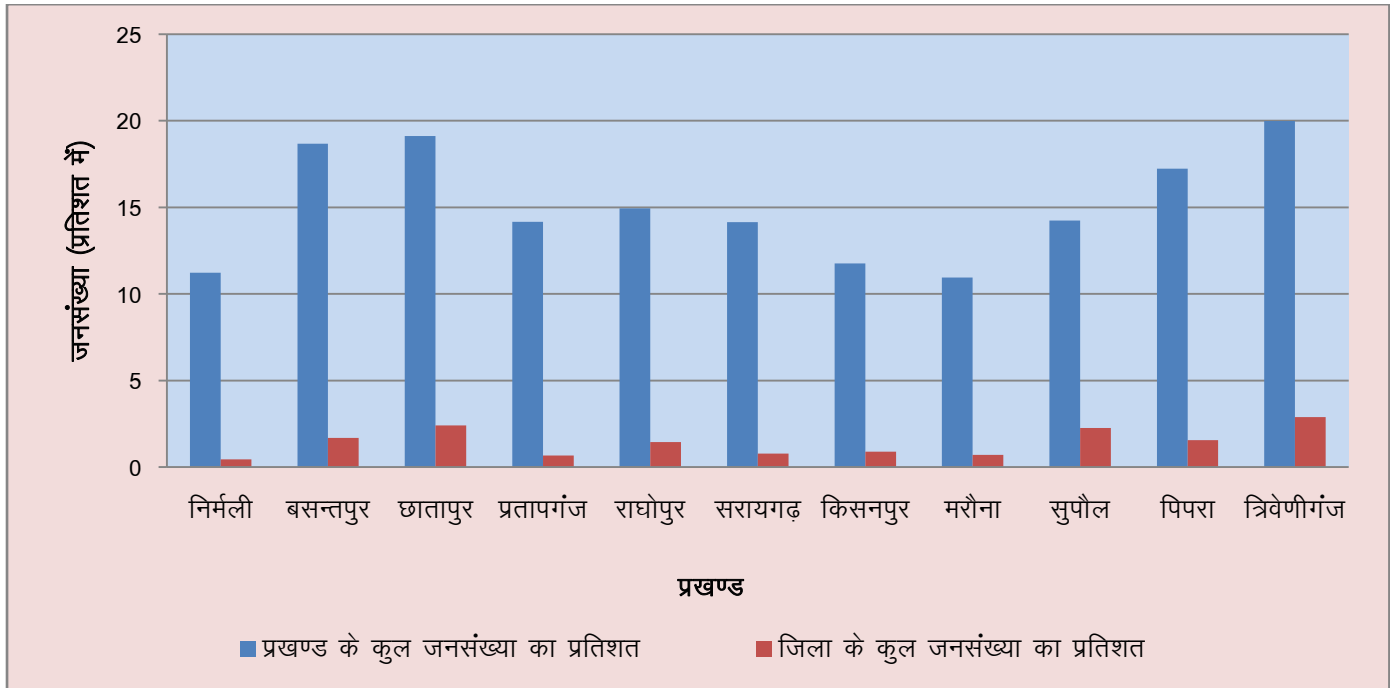


Fig. – 2

तालिका 2 में सुपौल जिला में अनुसूचित जाति की संख्या को जिला के कुल जनसंख्या का प्रतिशत तथा प्रखण्ड के कुल जनसंख्या प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। जिला के कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम निर्मली में 0.45 प्रतिशत है जबकि सबसे अधिक त्रिवेणीगंज में 2.88 प्रतिशत है। इसी प्रकार अन्य प्रखण्डों में प्रतापगंज प्रखण्ड में 0.67 प्रतिशत, मरौना प्रखण्ड में 0.71 प्रतिशत, सरायगढ़ प्रखण्ड में 0.77 प्रतिशत, किसनपुर प्रखण्ड में 0.88 प्रतिशत, राधोपुर प्रखण्ड में 1.45 प्रतिशत, पिपरा प्रखण्ड में 1.55 प्रतिशत, बसन्तपुर प्रखण्ड में 1.69 प्रतिशत तथा छातापुर प्रखण्ड में 2.41 प्रतिशत पाया जात है। प्रखण्ड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वितरण में भी असमानता पायी जाती है जिसे निम्नांकित समूहों में बाँटा जा सकता है –

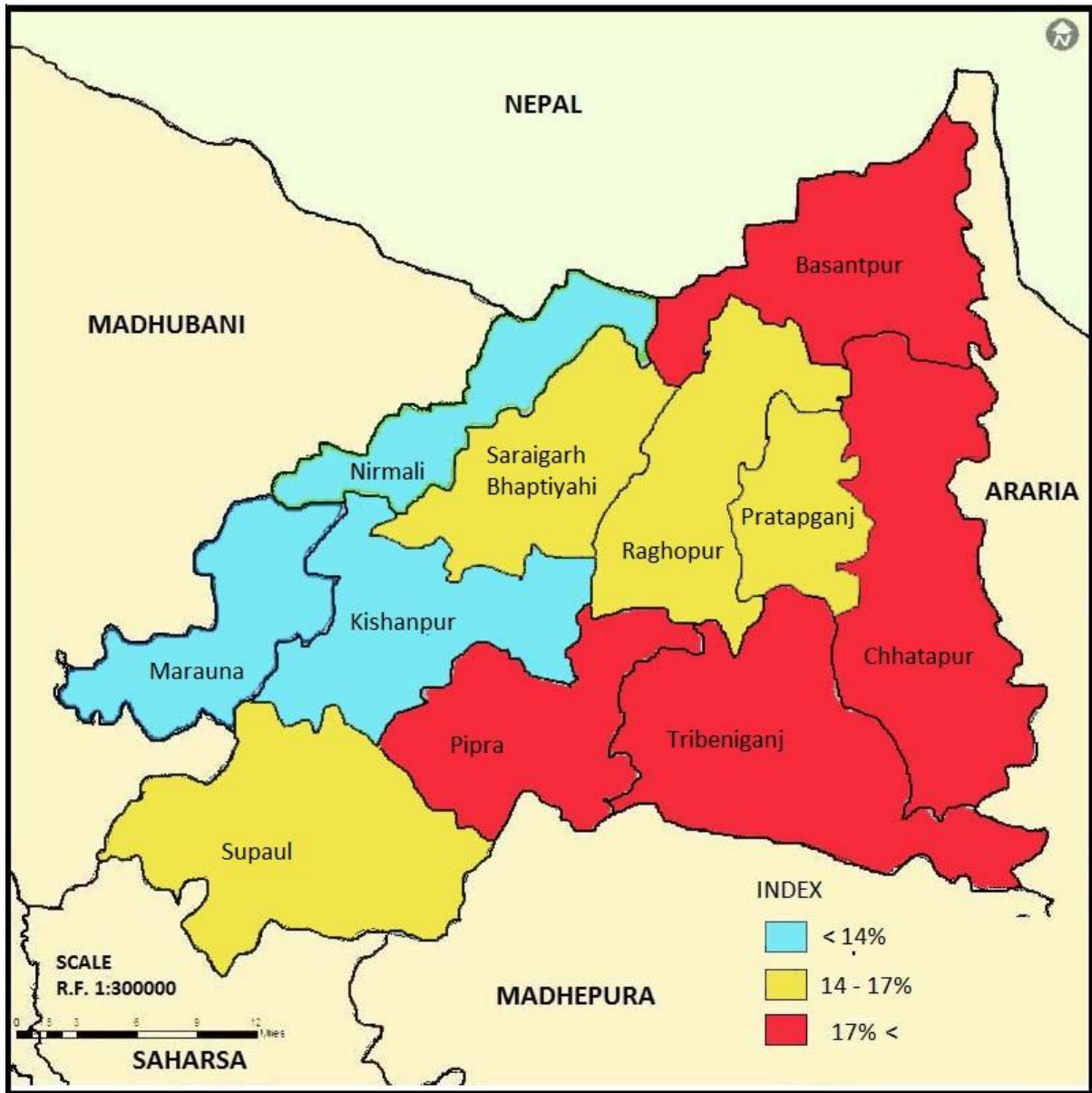
तालिका – 3

सुपौल जिला में प्रखण्ड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का वितरण समूह वर्ग

क्रम संख्या	समूह वर्ग	प्रखण्डों की आवृत्ति	प्रखण्डों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1.	< 14%	03 (कुल आवृत्ति का 27.27 प्रतिशत)	मरौना 10.95, निर्मली 11.23, किसनपुर 11.70
2.	14 – 17%	04 (कुल आवृत्ति का 36.36 प्रतिशत)	सरायगढ़ भवटियाही 14.15, प्रतापगंज 14.16, सुपौल 14.23, राधोपुर 14.95
3.	17%<	04 (कुल आवृत्ति का 36.36 प्रतिशत)	पिपरा 17.23, बसन्तपुर 18.68, छातापुर 14.12, त्रिवेणीगंज 19.18

स्रोत – भारत की जनगणना 2011, बिहार श्रृंखला 11

सुपौल जिला में प्रखण्ड के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का वितरण समूह वर्ग



Map – 3

तालिका 3 में प्रखण्डों की कुल संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की संख्या को दर्शाया है, जिसे तीन वर्ग समूह में रखा गया है जो निम्नांकित है –

1. 14 प्रतिशत से कम संख्या वाले प्रखण्ड :-

इसके अन्तर्गत 03 प्रखण्ड सम्मिलित है जो कुल प्रखण्डों का 27.27 प्रतिशत है। जिसमें मरौना 10.94 प्रतिशत निर्मली 11.23 प्रतिशत तथा किसनपुर 11.70 प्रतिशत है। अन्य वर्ग समूहों की तुलना में यहाँ न्यून संख्या पायी जाती है।

2. 14 से 17 प्रतिशत संख्या वाले प्रखण्ड :-

इस वर्ग समूह में 04 प्रखण्ड सम्मिलित है जिसमें सरायगढ़ भवटियाही 14.15 प्रतिशत, प्रतापगंज प्रखण्ड 14.16 प्रतिशत, सुपौल प्रखण्ड 14.16 प्रतिशत तथा राघोपुर 14.95 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का वसाव है, जो कुल प्रखण्डों का 36.36 प्रतिशत प्रखण्ड है।

3. 17 प्रतिशत से अधिक संख्या वाले प्रखण्ड :-

इस वर्ग समूह में कुल प्रखण्डों का 36.36 प्रतिशत प्रखण्ड सम्मिलित है, जिसमें पिपरा प्रखण्ड 17.23 प्रतिशत, बसन्तपुर 18.68 प्रतिशत, छातापुर 19.12 प्रतिशत, त्रिवेणीगंज 19.18 प्रतिशत प्रखण्ड है। इस वर्ग में 04 प्रखण्ड आते हैं।

अनुसूचित जातियों में शिक्षा का विकास अन्य वर्गों की अपेक्षा काफी कम है। अध्ययन क्षेत्र में केवल 39 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों सरकारी प्रयास एवं आरक्षण नीति से लाभान्वित हेतु शिक्षा का विकास हो रहा है। आरक्षण का लाभ कुछ ही परिवारों तक सीमित है, जो खासकर पहले से लाभ ले रहे हैं। जिससे वास्तविक रूप से पिछले दलित अभी भी उसी अवस्था में है। यद्यपि प्रधानमंत्री आवास, सड़क योजना रोजगार आदि का लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह सुधार समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा कम है। छुआ-छुत प्रायः समाप्त हो चुका है। केवल कुछ पिछड़े क्षेत्रों में न्यून पैमाने पर यह भावना अभी भी है।

सुझाव एवं निष्कर्ष :-

अध्ययन क्षेत्र सुपौल जिला में अनुसूचित जातियाँ अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। इनके उत्थान के लिए सभी प्रकार के सरकारी प्रयास जारी हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के कारण योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था के बावजूद भी ये लोग शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं। इसका मुख्य कारण आरक्षण का लाभ केवल कुछ ही परिवारों को मिलता है, अन्य लोग सरकारी नौकरी का आशा नहीं रखते, वरन् इनकी मासिकता शारीरिक श्रम की होती है। दलित गरीब लोगों के उत्थान हेतु आरक्षण से लाभान्वित लोगों को आरक्षण से अलग रखा जाय तथा जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वैसे परिवारों को यह लाभ दिया जाय। लोगों अपने अधिकार तथा सरकारी लाभ के प्रति जागरूक किया जाय। जिससे आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास संभव हो सके।

—: संदर्भ सूची :-

1. भारत की जनगणना 2011, बिहार श्रृंखला 11
2. Chandna R. C. – Introduction of Population Geography Kalyani Publication New Delhi.
3. Sharilf A – Indian Human development Report.
4. Gosal G. S. – Literacy in India An Interpretative study Rural Society.